



विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025



संकल्प पत्र
डाउनलोड करने हेतु
QR कोड को स्कैन करें



कमल का बटन दबाएं



भाजपा को जिताएं



भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश



विषय सूची

01	प्रदेश अध्यक्ष का संदेश	06
02	संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष का संदेश	07
03	दिल्ली संकल्प पत्र समिति सदस्य	08
04	विकसित दिल्ली के लिए हमारे 16 संकल्प	09-11
05	दिल्ली में केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियां	12
06	दिल्ली में 'आप-दा' का कुप्रबंधन	13
07	कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था	16-17
08	गरीब कल्याण	18
09	जे.जे. क्लस्टरों में सभी बुनियादी सुविधाएं	19-21
10	अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण	22-23
11	सशक्त नारी	24-27
12	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	28-29
13	आरोग्य प्रदेश, सुखमय नागरिक	30-31
14	उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था	32-35
15	सक्षम युवा	36-37
16	सबका साथ सबका विकास	38-41
17	प्रबल अर्थव्यवस्था	42-43
18	व्यापारी वर्ग का कल्याण	44-45
19	सभी के लिए ईज ऑफ लिविंग	46-47
20	ग्रामीण दिल्ली का विकास	48-49
21	विश्व स्तरीय परिवहन	50-53
22	सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और पर्यटन का विकास	54-55
23	स्वच्छ एवं हरित दिल्ली	56-57

प्रदेश अध्यक्ष का संदेश

प्रिय दिल्लीवासियों,
नमस्कार,

भारतीय जनता पार्टी 'विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025' को लेकर आपके सामने आई है, जो दिल्ली के उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप है। यह संकल्प पत्र केवल एक चुनावी घोषणापत्र नहीं, बल्कि दिल्ली के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह पत्र उन वादों का प्रतिफल है जो भाजपा दिल्लीवासियों से करती है—वो वादे जो पिछले दस वर्षों में आप-दा ने कभी पूरे नहीं किए।

दिल्ली में आप-दा का शासनकाल, भ्रष्टाचार, घोटालों और प्रशासनिक विफलताओं से भरा रहा है। शराब घोटाला, भ्रष्टाचार के आरोप (शीशमहल का निर्माण), वित्तीय अनियमितताएं और प्रदूषण आदि समस्याओं ने दिल्लीवासियों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं वायु प्रदूषण आदि जैसे बुनियादी मुद्दों पर आप-दा का प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है।

अब भाजपा की सरकार बनने पर, हम दिल्ली को एक नई दिशा देंगे। हम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करेंगे, ताकि दिल्ली के हर नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। जल जीवन मिशन के तहत हम दिल्ली के हर घर स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही, हम 3.5 लाख गरीब परिवारों को अपना घर देंगे एवं महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता की योजना लागू करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक नई उम्मीद और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी, जो दिल्ली को प्रदूषण, भ्रष्टाचार और असुरक्षा से मुक्त कर एक समृद्ध और सुरक्षित राज्य बनाएगी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को जोड़ कर उन्हें हम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाएंगे। आइए, हम सब मिल कर दिल्ली को फिर से गौरवमयी और विकसित राज्य बनाएं।

धन्यवाद।

आपका,

वीरेंद्र सचदेवा

अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली



संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष का संदेश

नमस्कार,

सपने करेगी साकार, दिल्ली में भाजपा सरकार

महाभारत काल के इन्द्रप्रस्थ से लेकर आज तक की अपनी लम्बी विकास यात्रा में इस शहर ने कई मंजर देखे हैं, लेकिन यह बड़ी पीड़ा की बात है कि आज आप-दा के कारनामों की वजह से हमारी राजधानी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। आज इसकी गिनती दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में हो रही है। हवा में इतना जहर घुला हुआ है कि सांस लेना दूभर है। दिल्ली में आकर यमुना नदी एक जहरीले नाले में बदल गई है और गंदगी से वजवजा रही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 इस महानगर की गरिमा को लौटाने का एक महान अवसर लेकर आया है। अब बदलाव दिल्ली की चौखट पर दस्तक दे रहा है। देश की राजधानी की बदहाली के दिन खत्म होने का समय आ गया है। राजधानी के लोगों की आंखों में पलने वाले समृद्धि के सपनों में रंग भरने के लिए भाजपा लेकर आई है 'विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025'।

आइए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा सरकार चुनें और नए भारत की बेहतर दिल्ली बनाएं। आइए, अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, विकसित और सर्वश्रेष्ठ दिल्ली की सौगात सौंपें।

धन्यवाद।

जय हिन्द!

आपका,

रामवीर सिंह बिधूड़ी

संयोजक, चुनावी संकल्प पत्र समिति,

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली





दिल्ली संकल्प पत्र समिति सदस्य

संयोजक

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी

सदस्य

डॉ. हर्ष वर्धन

सरदार अरविन्दर सिंह लवली

श्री विजय गोयल

श्री सतीश उपाध्याय

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री प्रवेश साहिब सिंह

श्री अजय महावर

श्री प्रवीण शंकर कपूर

श्री अभिषेक टंडन

डॉ. राजकुमार फलवारिया

श्रीमती नीतू डबास

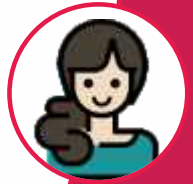


विकसित दिल्ली के लिए हमारे 16 संकल्प



हमारी सरकार न केवल मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा इन योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा।

हम महिला समृद्धि योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।



हम मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को ₹21,000 की सहायता एवं 6 पोषण किट प्रदान करेंगे।

हम गरीब परिवार की महिलाओं को ₹500 में एलपीजी (LPG) सिलेंडर और होली एवं दीपावली के अवसर पर एक-एक मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे।



हम पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को केंद्र सरकार द्वारा ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज और राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा।

हम 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं निशुल्क ओपीडी ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक सेवा उपलब्ध कराएंगे।



हम 60 से 70 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन को प्रति माह ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 करेंगे तथा 70+ वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं, निराश्रित एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन को प्रति माह ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 करेंगे।



हम जे.जे. क्लस्टर्स में अटल कैंटीन्स स्थापित करेंगे जहां ₹5 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।



हमारी सरकार दिल्ली की स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी, परिवहन आदि से जुड़ी समस्याओं का बहाना, बहस या दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय, उसका पड़ोसी राज्यों, एमसीडी (MCD), एनडीएमसी (NDMC) एवं केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके प्रभावी समाधान करेगी।



हम आप-दा के व्यापक कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाएंगे एवं डीटीसी (DTC), मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम, एक्साइज पॉलिसी, जल बोर्ड, आदि से जुड़े घोटालों की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन करेंगे।



हम दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।



हम दिल्ली के युवाओं को राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम बनाने के लिए:

- एकमुश्त ₹15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे
- परीक्षा केंद्र तक की यात्रा लागत और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट्स तक प्रतिपूर्ति करेंगे



हम दिल्ली में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आईटीआई (ITI), स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रति माह ₹1,000 का स्टाइपेंड प्रदान करेंगे।

हम ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए 'वेलफेयर बोर्ड' बनाएंगे, जिसमें उन्हें ₹10 लाख तक का जीवन बीमा, ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा, ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को रियायती वाहन बीमा और डोमेस्टिक वर्कर्स को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी।

























हम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करेंगे।

हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पात्र किसानों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे, साथ ही ₹6,000 की वार्षिक सहायता को बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष करेंगे।



दिल्ली में केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

केंद्र सरकार ने दिल्ली के नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन किया है।

-  75 लाख नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज
-  1,731 कॉलोनियों को नियमित करने एवं 40 लाख लोगों को पीएम-उदय योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की
-  पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 29,000 से ज्यादा आवास एवं 1,600+ परिवारों को 'जहां झुग्गी वहां मकान' के अंतर्गत फ्लैट प्रदान किए जा रहे हैं
-  3 लाख+ गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रति माह ₹5,000
-  2.6 लाख गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्वला योजना के अंतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन
-  ₹19,655 करोड़ का ऋण पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मिला
-  5,000+ एससी छात्रों को श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत ₹7.5 करोड़ की छात्रवृत्ति एवं डॉ. अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का निर्माण
-  1.9 लाख स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ₹295 करोड़ का ऋण
-  12,000+ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वार्षिक ₹6,000
-  4 लाख+ केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनर्स को मिलेगा आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत लाभ
-  पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के विकास के लिए ₹68,000 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूर्ण
-  ₹7,500 करोड़ से द्वारका एक्सप्रेसवे, भारत का पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, का निर्माण
-  दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण
-  आरआरटीएस (RRTS) के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक के विस्तार को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है
-  ₹6,230 करोड़ की लागत से दिल्ली मेट्रो फेज-IV के 26.5 किमी रिठाला-कुंडली सेक्शन की आधारशिला
-  ₹920 करोड़ के निवेश से प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का निर्माण
-  भारत के पहले एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालन
-  ₹4,600 करोड़ की लागत से दिल्ली के पहले नमो भारत कॉरिडोर की स्थापना
-  ₹140 करोड़ की लागत से नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला
-  फेम II (FAME II) योजना के तहत दिल्ली में 1,400 ई-बसों का संचालन
-  ₹960 करोड़ से दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत 642+ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूर्ण
-  यशोभूमि और भारत मंडपम की स्थापना से दिल्ली बना भारत का सबसे बड़ा एमआईसीई (MICE) पर्यटन केंद्र

दिल्ली में 'आप-दा' का कुप्रबंधन



जन कल्याण के खिलाफ आप-दा

- दिल्ली में महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 देने का वादा आज भी अधूरा
- आप-दा ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड एवं 300 ऑटो स्टैंड स्थापित करने में रही विफल
- आप-दा ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन पर लगाई रोक



आप-दा सरकार, घोटाले की सरकार

- दिल्ली जल बोर्ड में ₹28,000 करोड़ की अनियमितता, राशन वितरण में ₹5,400 करोड़ का घोटाला
- क्लासरूम्स के निर्माण में ₹13,000 करोड़ का घोटाला
- मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी लैब टेस्ट का घोटाला
- पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता के पैसे से बनाया 50,000 गज का आलीशान 'शीशमहल'



केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों में डाली बाधाएं

- आयुष्मान भारत लागू न करके 80 लाख नागरिकों को ₹5 लाख के स्वास्थ्य बीमा से रखा वंचित
- जल जीवन मिशन लागू न करके नागरिकों से हर घर नल से जल का छीना हक
- प्रधानमंत्री आवास योजना समय पर लागू न करके 10 लाख नागरिकों से छीना आवास का हक



स्वच्छ दिल्ली का वादा, दूषित दिल्ली की हकीकत

- ₹8,500 करोड़ खर्च के बाद भी आप-दा यमुना की सफाई करने में रही विफल

- आप-दा की अनदेखी से दिल्ली का एक्यूआई 1,200 पार, करोड़ों लोगों को सांस-संबंधी बीमारियों ने जकड़ा
- आप-दा ने भलस्वा, गाजीपुर और ओखला में कचरे के पहाड़ खड़े किए, वही केंद्र सरकार ने बांसेरा लैंडफिल को पार्क में परिवर्तित किया
- आप-दा के राज में दिल्ली के नागरिकों को सबसे दूषित पानी मिला, साथ ही टैंकर माफियाओं का आतंक छाया
- आप-दा की खराब ड्रेनेज व्यवस्था से बारिश में जलभराव और करंट से कई मौतें, 3 यूपीएससी छात्रों की डूबकर गई जान



दिल्ली की खस्ता शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था

- आप-दा द्वारा करोड़ों रुपए आवंटित करने के बावजूद मोहल्ला क्लिनिकों की दयनीय हालत एवं फर्जी दवाई वितरण से 3 बच्चों की मौत
- ₹5,590 करोड़ आवंटित करने के बावजूद 24 प्रस्तावित अस्पतालों में से ज्यादातर अस्पताल सिर्फ कागज पर मौजूद
- आप-दा 2015-2022 में 500 विद्यालय और 20 कॉलेजों का वादा कर केवल 63 स्कूल और 1 सरकारी कॉलेज खोल पाई
- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, 2023-24 में, कक्षा 9 में 1 लाख से अधिक छात्र फेल, वही 2021-22 में 28,531 फेल



आप-दा के वित्तीय कुप्रबंधन से दिल्ली घाटे में

- 31 वर्षों में पहली बार, आप-दा के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को राजस्व घाटे का करना पड़ा सामना
- आप-दा ने वित्तीय कुप्रबंधन के चलते केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से ₹10,000 करोड़ का मांगा कर्ज
- दिल्ली जल बोर्ड पिछले 10 वर्षों में ₹73,000 करोड़ के कर्ज में, साथ ही 2016 से नहीं की बैलेंस शीट प्रस्तुत



हमारी सरकार न केवल
मौजूदा कल्याणकारी
योजनाएं जारी रखेगी,
बल्कि उन्हें और अधिक
प्रभावी बनाया जाएगा
तथा इन योजनाओं में
भ्रष्टाचार को समाप्त
किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

“

हम संकल्प लेते हैं कि हम एक ऐसी विकसित दिल्ली बनाएंगे जिस पर पूरा भारत गर्व कर सके। दिल्ली न केवल भारत के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होगा, बल्कि विश्व स्तरीय अधोसंरचना, उत्तम कानून और न्याय व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण और उत्कृष्ट शहरी सेवाओं का आदर्श भी होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से यह राजधानी, भारत की विकास गाथा का नेतृत्व करेगी, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।”

”





कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था

आप-दा ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को अराजकता और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है। उनके मंत्री जेल गए, और जनता के पैसों का दुरुपयोग करके नेताओं ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी और चुनावों में इस पैसे का प्रयोग किया। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस

- हम आप-दा के व्यापक कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाएंगे एवं डीटीसी (DTC), मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम, एक्साइज पॉलिसी, जल बोर्ड, आदि से जुड़े **घोटालों की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन** करेंगे।
- हम आप-दा द्वारा रोकी गई **कैग (CAG) रिपोर्ट को विधानसभा के पहले सत्र में पेश** करेंगे।
- हम 2015 से दिल्ली में चली आ रही गलत शासन व्यवस्था को उजागर करते हुए, **श्वेत पत्र** प्रकाशित करेंगे, जो न केवल भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी गलतियों का दोबारा कभी सामना न करना पड़े।
- हम आप-दा के **लिकर पॉलिसी** की जांच में तेजी लाने के लिए सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) को पूरी सहायता प्रदान करेंगे, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और इस घोटाले से हुए राजस्व नुकसान की पूरी वसूली की जा सके। साथ ही, हम मौजूदा शराब लाइसेंसिंग नीति को समाप्त करके एक **नई, पारदर्शी और जवाबदेह नीति** लागू करेंगे।
- हम **शीश महल घोटाले** में वित्तीय अनियमितताओं की समयबद्ध जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक **एसआईटी (SIT) का गठन** करेंगे।
- हम आप-दा के अंतर्गत **दिल्ली जल बोर्ड को दिए गए ₹28,000 करोड़ से अधिक के बजट का विस्तृत वित्तीय ऑडिट** करेंगे और वित्तीय अनियमितताओं को सामने लाएंगे एवं बोर्ड के कामकाज में सुधार लाएंगे।
- हम दिल्ली के सरकारी **विद्यालयों एवं कक्षाओं के निर्माण और फर्जी शिक्षकों (घोस्ट टीचरों) की नियुक्ति के घोटालों** की समयबद्ध जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक **एसआईटी (SIT) का गठन** करेंगे।
- हम **मोहल्ला क्लिनिक** घोटाले की समयबद्ध जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक **एसआईटी (SIT) का गठन** करेंगे, जो इन मुद्दों पर जांच करेगी:
 - प्रत्येक वर्ष करोड़ों आवंटित होने के बावजूद मोहल्ला क्लिनिकों की दयनीय हालत
 - मोहल्ला क्लिनिकों द्वारा किए गए 65,000 फर्जी लैब टेस्ट का घोटाला

- हम दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में पैनिक बटन और सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक एसआईटी (SIT) का गठन करेंगे।
- हम घरेलू उपभोक्ताओं के बड़े बिजली बिलों की जांच कराएंगे।
- हम प्रदूषण के लिए जिम्मेदार आप-दा को सामने लाने के लिए दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में एसआईटी (SIT) का गठन करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित जांच होगी:
 - हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना की सफाई करने में नाकामी
 - दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में नाकामी
- हम 2017-2024 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के घाटे में हुई वृद्धि पर श्वेत पत्र जारी करेंगे।
- हम आप-दा के द्वारा भाई-भतीजावाद के आधार पर गैर-कानूनी नियुक्तियों को उजागर करने वाली शृंगलू कमेटी रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर, केंद्र सरकार के सहयोग से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जांच कराएंगे।
- हम दिल्ली डिस्कॉम द्वारा दिल्ली सरकार को बकाया ₹26,000 करोड़ की समयबद्ध जांच और रिकवरी कराएंगे।

सुशासन

- हमारी सरकार दिल्ली की स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी, परिवहन आदि से जुड़ी समस्याओं का बहाना, बहस या दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय, उसका पड़ोसी राज्यों, एमसीडी (MCD), एनडीएमसी (NDMC) एवं केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके प्रभावी समाधान करेगी।
- हम वर्तमान सीएम (CM) हेल्पलाइन के दायरे का विस्तार करेंगे और उसके अंतर्गत नियमित रूप से सुशासन ड्राइव्स और शिविर आयोजित करेंगे। इसके साथ ही, प्रत्येक वार्ड में मुख्यमंत्री शिविर आयोजित करेंगे।
- हम सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी, भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन एवं यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन का व्यापक पैमाने पर उपयोग करेंगे।
- हम पुरानी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के पुनर्विकास के लिए सभी स्वीकृति समयबद्ध तरीके से प्रदान करेंगे।
- हम सर्किल रेट को न्यायसंगत बनाएंगे और इनकी समयबद्ध समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- हम 24x7 रात्रि गश्त सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिल कर डेल्टा 48 यूनिटों में पुलिस बल का विस्तार करेंगे।
- हम न्यायिक आधारभूत संरचना में सुधार के लिए एक विशेष कोष बनाएंगे। इसके अंतर्गत:
 - न्यायालय के वर्तमान भवनों का उन्नयन करेंगे
 - न्यायालयों में चेम्बर्स की संख्या बढ़ाएंगे
 - फास्ट ट्रैक कोर्ट, वाणिज्यिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और लोक अदालत की संख्या बढ़ाएंगे
 - अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए चेम्बर एवं स्मार्ट लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे
 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लॉ ग्रेजुएट्स के लिए फेलोशिप शुरू करेंगे
- हम जिला एवं सत्र न्यायालयों में न्यायाधीशों के सभी लंबित रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरेंगे।





गरीब कल्याण

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत तथा जल जीवन मिशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने लाखों गरीब परिवारों की मदद की है और उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। दिल्ली में आप-दा ने अपनी तुच्छ राजनीति के कारण केंद्र सरकार की अधिकांश जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में इन प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और वंचितों की जरूरतों को सबसे आगे रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

- हम पहली कैबिनेट बैठक में **आयुष्मान भारत योजना** लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को **केंद्र सरकार द्वारा ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज और राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज** प्रदान किया जाएगा।
- हम सभी गरीब परिवारों को **रियायती दर पर डायग्नोस्टिक सेवाएं** उपलब्ध करवाएंगे।
- हम पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अंतर्गत **सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा** प्रदान करेंगे।
- हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत **75 लाख लाभार्थियों को 5 वर्ष तक मुफ्त राशन** उपलब्ध कराते रहेंगे।
- हम **नागरिकों को मुफ्त जल** उपलब्ध कराते रहेंगे।
- हम वर्तमान **राशन वितरण प्रणाली (पीडीएस) को प्रभावशाली** बनाएंगे जिसके अंतर्गत **नए राशन कार्ड** बनाने के लिए शिविर लगाएंगे और जो नागरिक अभी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल करेंगे।

- हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए **EWS आयोग** का गठन करेंगे।
- हम दिल्ली में **रैन बसेरों की पर्याप्त संख्या** सुनिश्चित करेंगे एवं उनमें **सभी मूलभूत सुविधाएं** प्रदान करेंगे।



जे.जे. क्लस्टरों में सभी बुनियादी सुविधाएं

आप-दा ने दिल्ली के जे.जे. क्लस्टर निवासियों के कल्याण को बार-बार अनदेखा किया है, जिससे वह आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। भाजपा जे.जे. क्लस्टर निवासियों के कल्याण और विकास को प्राथमिकता देकर उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास, पीएम श्री और पिंग पुलिस बूथ जैसी योजनाओं के माध्यम से, हम जे.जे. क्लस्टर के लिए किफायती आवास, उत्तम शिक्षा, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे।

आधारभूत संरचना

- हम जे.जे. क्लस्टरों में **अटल कैंटीन्स** स्थापित करेंगे जहां **₹5 में पौष्टिक भोजन** उपलब्ध कराया जाएगा।
- हमने **कालकाजी क्षेत्र एवं अशोक विहार** में **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** के अंतर्गत जे.जे. क्लस्टरों के निवासियों को फ्लैट प्रदान किए हैं। हम केंद्र सरकार के साथ मिल कर जे.जे. क्लस्टरों और वंचित समाजों के निवासियों को अतिरिक्त **3.5 लाख पक्के घर** उपलब्ध कराएंगे।
- हम जे.जे. क्लस्टर में **स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम** स्थापित करेंगे।
- हम जे.जे. क्लस्टर के निवासियों को **मुफ्त जल उपलब्ध कराते रहेंगे**।
- हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत जे.जे. क्लस्टर में बढ़ते दूषित पानी की समस्याओं को दूर करेंगे, साथ ही **हर घर नल से स्वच्छ जल** उपलब्ध करवाएंगे।
- हम **टैंकर माफिया को खत्म** करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम प्रत्येक जे.जे. क्लस्टर निवासी को मुफ्त प्राथमिक इलाज देने के लिए क्लस्टरों के नजदीक **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** स्थापित करेंगे।
- हम **दिल्ली नगर निगम** के साथ मिल कर **दिल्ली जे.जे. क्लस्टर सेनिटेशन टास्क फोर्स** का गठन करेंगे, जिसके अंतर्गत :
 - हम **सार्वजनिक कूड़ेदानों** की संख्या बढ़ाएंगे और साथ ही **सूखा और गीला कचरा** अलग-अलग करने की व्यवस्था लागू करेंगे।
 - **अतिरिक्त सामुदायिक शौचालय** बनाएंगे और मौजूदा शौचालयों की **देखरेख** सुनिश्चित करेंगे, ताकि स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
- हम **पीएम श्री** की तर्ज पर **सीएम श्री योजना** की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत जे.जे. क्लस्टरों में आधुनिक कक्षाओं, योग्य शिक्षकों आदि के साथ **नए विद्यालय खोले जाएंगे और वर्तमान सरकारी विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा**।
- हम केंद्र सरकार के सहयोग से तीन महीने के अंदर दिल्ली के सभी जे.जे. क्लस्टर में **ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन शिविर** लगाएंगे, ताकि **आयुष्मान भारत, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना जैसी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण** सुनिश्चित किया जा सके।
- हम दिल्ली की जे.जे. क्लस्टरों में **सुषमा स्वराज सदन पुस्तकालय** स्थापित करेंगे।
- हम प्रत्येक जे.जे. क्लस्टर में **शटल सेवाएं** शुरू करेंगे, जिनमें ई-रिक्शा, ई-बाइक आदि शामिल होंगे, जो जे.जे. क्लस्टरों के निवासियों को मेट्रो स्टेशनों, बस स्टॉप आदि से जोड़ेगी। इन सुविधाओं में महिलाओं के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।

सुरक्षित वातावरण

- हम सुरक्षा बढ़ाने के लिए **जे.जे. क्लस्टर्स में पुलिस चौकियां** स्थापित करेंगे।
- हम जे.जे. क्लस्टर्स में **सी.सी.टी.वी. कैमरों का नेटवर्क स्थापित करेंगे**, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सके और अपराधों पर लगाम लग सके।
- हम **पुलिस बल में** जे.जे. क्लस्टर्स के निवासियों के प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए **विशेष प्रशिक्षण** कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- हम स्थानीय पुलिस और निवासियों के साथ मिल कर जे.जे. क्लस्टर्स को 'क्राइम-फ्री जोन' बनाने के लिए **क्लस्टर सुरक्षा समितियां** स्थापित करेंगे।





अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण

आप-दा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में विफल रही है और 24x7 बिजली, साफ-सफाई, नियमित जल आपूर्ति जैसी उनकी बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा की है। भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

- हम दिल्ली में 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान करेंगे। इन कॉलोनियों के निवासियों को अपने घरों का पूर्ण स्वामित्व अधिकार मिलेगा और वे आवास मंत्रालय और दिल्ली के बिल्डिंग बाय लॉ के प्रावधानों के अनुसार अपने घरों का निर्माण, निर्माण या पुनर्निर्माण कर सकेंगे।
- हम केंद्र सरकार के सहयोग से एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिसके माध्यम से सरकार की जमीन पर स्थित सभी पात्र अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
- हम कॉलोनी अपग्रेडेशन कमीशन का गठन करेंगे, जो इन कॉलोनियों में सामुदायिक केंद्र, सड़क, जल निकासी व्यवस्था, कचरा संग्रहण और सीवर जैसी जन-सुविधाएं सुनिश्चित कराएंगे।
- हम प्रत्येक निवासी की बुनियादी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के नजदीक आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर स्थापित करेंगे।
- हम जल जीवन मिशन को लागू करके अनधिकृत कॉलोनियों में हर घर नल से जल सुनिश्चित करेंगे, साथ ही हम टैंकर माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे।







सशक्त नारी

आप-दा अपने बड़े-बड़े दावों के बावजूद महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर विफल रही है। हम महिलाओं के नेतृत्व में अपने विकास के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अन्य भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। हम दिल्ली में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण

- हम **महिला समृद्धि योजना** शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवार की महिलाओं को **प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता** प्रदान करेंगे।
- हम दिल्ली सरकार की नौकरियों में **महिलाओं को 33% आरक्षण** देंगे।
- हम स्वयं सहायता समूहों (SHG) में काम करने वाली महिलाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए **ई-कॉमर्स एवं क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी** करेंगे, साथ ही उन्हें मार्केटिंग की सहायता भी प्रदान करेंगे।
- हम स्वयं सहायता समूहों (SHG) में काम करने वाली महिलाओं को **₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण** उपलब्ध कराएंगे।
- हम महिलाओं के लिए **मुफ्त डीटीसी (DTC) बसों की सुविधा** जारी रखेंगे।

- हम दिल्ली सरकार के विद्यालयों से **12वीं कक्षा पास करने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर** प्रदान करेंगे।
- हम **1,000 महिला ड्राइवर्स को पिंक ई-ऑटो** खरीदने के लिए **80% तक सब्सिडी** देंगे।

सामाजिक सशक्तिकरण

- हम गरीब परिवार की **महिलाओं को ₹500 में एलपीजी (LPG) सिलेंडर और होली एवं दीपावली के अवसर पर एक-एक मुफ्त सिलेंडर** उपलब्ध कराएंगे।
- हम **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों की **बेटियों की शादी के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता** प्रदान करेंगे।
- हम **विधवा, निराश्रित, परित्यक्त आदि महिलाओं को मिलने वाली पेंशन को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह** करेंगे।

विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं

- हम **मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना** के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को **₹21,000** की सहायता एवं **6 पोषण किट** प्रदान करेंगे।
- हम आयुष्मान भारत योजना में शामिल सभी सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए **मुफ्त सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग** की व्यवस्था करेंगे।
- हम महिलाओं के लिए **सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और फीडिंग रूम** जैसी सुविधाओं से पर्याप्त **250 पिंक पब्लिक शौचालयों** का निर्माण करेंगे।
- हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का **मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹12,000**, आंगनवाड़ी सहायकों का **मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹7,000** और आशा कार्यकर्ताओं का **मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹6,000** करेंगे, एवं उनकी स्वास्थ्य और जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे।

सुरक्षित वातावरण

- हम केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके **एंटी रोमियो स्क्वाड** को सभी सार्वजनिक स्थानों पर तैनात करेंगे।
- हम प्रदेश में **सी.सी.टी.वी. कैमरों का नेटवर्क स्थापित** करके सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके **झलकारी बाई बटालियन** की स्थापना करेंगे, जो दिल्ली की पहली महिला पुलिस बटालियन होगी।









वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन न होने और मोहल्ला क्लीनिकों के खराब रखरखाव के कारण, वरिष्ठ नागरिकों को अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के साथ समान व्यवहार और उनकी उचित देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे, बेहतर सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगे और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेंगे।

- हम 60 से 70 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन को प्रति माह ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 करेंगे तथा 70+ वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को प्रति माह ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 करेंगे।
- हम 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं निशुल्क ओपीडी ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक सेवा उपलब्ध कराएंगे।
- हम वरिष्ठ नागरिकों को 24x7 आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिरियाट्रिक एम्बुलेंस का नेटवर्क शुरू करेंगे।
- हम सभी सरकारी अस्पतालों में नियमित रूप से मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं दवाएं उपलब्ध कराएंगे।
- हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन सहायक उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे।
- हम सभी जिलों में चिकित्सा सुविधा, योग, फिजियोथेरेपी सेंटर, मनोरंजन एवं आर्थिक और डिजिटल काउंसलिंग सुविधा के साथ वयोश्री परिसरों की स्थापना करेंगे।
- हम वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्टफोन, इंटरनेट बैंकिंग एवं सरकारी सेवाओं जैसी ऑनलाइन सुविधाओं से जोड़ने और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएं शुरू करेंगे।
- हम गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को सीनियर एबल सिटीजन्स रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्रिटी (SACRED) पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।





आरोग्य प्रदेश, सुखमय नागरिक

मोहल्ला क्लीनिकों पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद, वह अभी भी नाकाम हैं और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे और सभी स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को बेहतर करेंगे।

- हम पहली कैबिनेट बैठक में **आयुष्मान भारत योजना** लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को **केंद्र सरकार द्वारा ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज और राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज** प्रदान किया जाएगा।
- हम निष्क्रिय और बंदहाल पड़े **मोहल्ला क्लीनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों** में परिवर्तित करके, निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे:
 - गर्भावस्था और नवजात शिशु के चिकित्सा की व्यवस्था
 - ओपीडी की व्यवस्था
 - संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों की जांच एवं उनके इलाज की व्यवस्था
- हम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (ABHIM) के माध्यम से **दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार** करेंगे।
- हम **हर जिले में 1 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल** स्थापित करेंगे।
- हम दिल्ली में **7 नए मेडिकल कॉलेज एवं नए नर्सिंग, फार्मसी और पैरामेडिकल कॉलेज** स्थापित करेंगे।
- हम डॉक्टरों, नर्सों, लैब तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के **रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती** करेंगे।
- हम डॉक्टरों की **सुरक्षा के लिए नया कानून लाएंगे और उसे सख्ती से लागू** करेंगे।
- हम **500 नए जन औषधि केंद्र** खोलकर नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं सस्ते में उपलब्ध कराएंगे।
- हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी **सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा** प्रदान करेंगे।
- हम दिल्ली को **डेंगू मुक्त बनाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन करेंगे एवं इस दिशा में समयबद्ध तरीके से काम करेंगे।







उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा में सुधार करने के दावों के बावजूद, आप-दा के सरकारी विद्यालय भीड़भाड़ और अपर्याप्त संसाधनों से जूझ रहे हैं। हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय की आधारभूत संरचना, छात्र कल्याण और शिक्षक प्रशिक्षण के सुधार में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम कौशल-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- हम दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को **केजी से पीजी तक** सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
- हम पीएम श्री की तर्ज पर **सीएम श्री योजना** की शुरुआत करेंगे जिसके अंतर्गत **100 सरकारी विद्यालयों** में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- हम **12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों** को पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) के साथ **पौष्टिक नाश्ता** भी उपलब्ध कराएंगे।
- हम **नई शिक्षा नीति 2020** का पूरा कार्यान्वयन करेंगे।
- हम मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के अंतर्गत **12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए मुफ्त लैपटॉप** प्रदान करेंगे।
- हम सभी सरकारी विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, बिजली और फर्स्ट-एड जैसी **बुनियादी सुविधाओं की 100% उपलब्धता** सुनिश्चित करेंगे।
- इसके साथ ही, हम **स्मार्ट विद्यालय मिशन** शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत:
 - कक्षा 9-12 तक की सभी कक्षाओं को **ऑडियो-विजुअल प्रोजेक्टर** से अपग्रेड करेंगे
 - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM) शिक्षा में **इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड** को शुरू करेंगे
 - कोडिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की व्यवस्था करेंगे
- हम प्रत्येक गरीब बच्चे को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए **प्री-प्राइमरी स्कूल** शुरू करेंगे।
- हम गरीब परिवारों, कश्मीर से विस्थापित परिवारों और 1984 दंगों के पीड़ित परिवारों के छात्रों के लिए **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस पर 50% तक की छूट** प्रदान करेंगे।

- हम गरीब परिवारों, कश्मीर से विस्थापित परिवारों और हम गरीब परिवारों, कश्मीर से विस्थापित परिवारों और 1984 दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए **मुख्य मंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि** की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत **कक्षा 8 तक के छात्रों को ₹2,500 और कक्षा 9-12 तक के छात्रों को ₹3,500 की वार्षिक वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।

उच्च शिक्षा

- हम दिल्ली की उच्च शिक्षा **जीईआर (GER) को 75% तक बढ़ाएंगे और 1 लाख सीटें** जोड़ेंगे:
 - दिल्ली विश्वविद्यालय के **वेस्ट कैम्पस** और **ईस्ट कैम्पस** की समयबद्ध स्थापना एवं अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैम्पस का विस्तार करेंगे
 - गुरु गोबिंद सिंह इंदरप्रस्थ विश्वविद्यालय जैसे मौजूदा विश्वविद्यालयों के अंतर्गत **नए महाविद्यालय की स्थापना** करेंगे, जिसमें कानून, डेंटल, फिजियोथेरेपी, व्यवसाय, इंजीनियरिंग, एवं नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रम शामिल होंगे
- हम जरूरतमंद छात्रों को **दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा** प्रदान करने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCCMC) वितरित करेंगे और उसमें **वार्षिक ₹4,000 क्रेडिट** करेंगे।
- हम विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करके **दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में विस्तृत विकास** करेंगे।

- हम केंद्र सरकार के साथ मिल कर **आईआईएम (IIM) दिल्ली की स्थापना** करेंगे।
- हम दिल्ली में **'एजु-सिटी' (Edu-City) स्थापित करेंगे**, जिसमें विश्व स्तरीय भारतीय एवं वैश्विक स्टेम (STEM) शिक्षण संस्थानों को कैम्पस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- हम केंद्र सरकार के साथ सहयोग से एजु-सिटी में आईआईटी (IIT) मद्रास रिसर्च पार्क की तर्ज पर **एक नया रिसर्च पार्क स्थापित करेंगे**।
- हम दिल्ली में **पीएम विद्यालक्ष्मी योजना** का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करके सभी पात्र विद्यार्थियों को एनआईआरएफ (NIRF) की शीर्ष 100 रैंकिंग वाले महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए **₹10 लाख तक का कोलैटरल फ्री ऋण** उपलब्ध करवाएंगे।

शिक्षक कल्याण

- हम **शिक्षा विभाग की रिक्तियों** को एक वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्पित हैं।
- हम दिल्ली में कार्यरत सभी शिक्षकों की **समस्याओं का त्वरित समाधान** करने हेतु **एक समिति** स्थापित करेंगे।
- हम सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों के **शिक्षकों के वेतन का समय पर भुगतान** करेंगे।









सक्षम युवा

आप-दा युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नौकरियां सृजित करने में नाकाम रही है। अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली के उभरते हुए एथलीट परेशान हैं। हम मजबूत रोजगार के अवसर सृजित करेंगे एवं खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे एवं उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

रोजगार के अवसर

- हम दिल्ली के 50,000 युवाओं को समयबद्ध तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे।
- हम दिल्ली के लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।
- हम प्रधानमंत्री इंटरशिप स्कीम के अंतर्गत प्रति माह ₹5,000 तक की वित्तीय सहायता और प्रत्येक इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान करेंगे।
- हम दिल्ली के युवाओं को नए युग के कौशल जैसे ग्रीन एनर्जी, 3-D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोग्रामिंग आदि में प्रशिक्षित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी कौशल योजना शुरू करेंगे।
- हम अरुण जेटली स्टार्टअप और इनोवेशन योजना शुरू करके नए स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे एवं नए इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करेंगे।
- हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को उत्कृष्ट कौशल केंद्रों में उन्नत करेंगे, साथ ही उन्हें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना और मजबूत इंडस्ट्री लिंकेज भी प्रदान करेंगे।

- हम बेरोजगारी एवं कौशल पर जानकारी एकत्रित करने के लिए दिल्ली में **स्किल सेन्सस** का आयोजन करेंगे, जिससे दिल्ली में रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- हम दिल्ली के युवाओं के लिए **सीएम गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम** शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत उन्हें विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर काम करने का अवसर मिलेगा।

स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

- हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत दिल्ली के :
 - विद्यालयों, महाविद्यालयों और स्थानीय क्लबों में व्यवस्थित रूप से **प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की खोज** करेंगे
 - विजेताओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे
- हम सभी **मौजूदा खेल परिसरों को उन्नत करेंगे** और उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक परिसरों में विकसित करेंगे।
- हम दिल्ली **ई-स्पोर्ट्स इनिशिएटिव** की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत:

- विभिन्न तकनीकी और गेमिंग कंपनियों के सहयोग से ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना की जाएगी
- वार्षिक दिल्ली ई-स्पोर्ट्स लीग का शुभारंभ किया जाएगा
- गेमिंग और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाएगा
- हम ₹100 करोड़ के निवेश से साहिब सिंह वर्मा एथलीट कल्याण योजना शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत:
 - योग्य राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एथलीटों को पौष्टिक भोजन के लिए प्रति दिन ₹500 प्रदान किए जाएंगे
 - राज्य-स्तरीय एथलीटों को ₹10 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा
 - एथलीटों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी
- हम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोच, ट्रेनर,

फिजियो तथा अन्य स्टाफ के कौशल विकास एवं सर्टिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे।

युवा कल्याण

- हम दिल्ली के युवाओं को राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सक्षम बनाने के लिए:
 - एकमुश्त ₹15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे
 - परीक्षा केंद्र तक की यात्रा लागत और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति करेंगे
- हम 'नशा मुक्त दिल्ली' के अंतर्गत 50 नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे और सभी ड्रग हॉट-स्पॉट में कड़ी निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे।





सबका साथ सबका विकास

आप-दा ने दिल्ली के वंचित समाजों की जरूरतों को नजरअंदाज किया है और उनके कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अनदेखा किया है। इसके परिणाम स्वरूप, अनेक लोग आवश्यक संसाधनों से वंचित रह गए हैं। आप-दा के संकीर्ण दृष्टिकोण ने दिल्ली के विकास में रुकावट डाली है और असंख्य परिवारों की आकांक्षाओं को अनदेखा किया है। इसके विपरीत, भाजपा सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत में विश्वास करती है। हम प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, दिल्ली की समृद्धि में भागीदार बनने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान करेंगे।

व्यावसायिक समूह

- हम सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए 'ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड' का गठन करेंगे जिसके अंतर्गत हम उन्हें:
 - ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे
 - उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे
 - रियायती वाहन बीमा प्रदान करेंगे
- हम सभी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए 'डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' का गठन करेंगे जिसके अंतर्गत हम उन्हें:
 - ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे
 - उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे
- मातृत्व लाभ के रूप में 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव प्रदान करेंगे
- हम सभी गिग वर्कर्स के लिए 'गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' का गठन करेंगे जिसके अंतर्गत हम उन्हें:
 - ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे
 - उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे
 - रियायती वाहन बीमा प्रदान करेंगे
- हम सभी टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए 'टेक्सटाइल वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' का गठन करेंगे जिसके अंतर्गत हम उन्हें:
 - ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे
 - उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे

- ₹15,000 तक का टूलकिट प्रोत्साहन देंगे
- हम सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 'स्ट्रीट वेंडर्स वेलफेयर बोर्ड' का गठन करेंगे जिसके अंतर्गत हम उन्हें:
 - ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे
 - उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे
 - स्पेशल वेंडिंग जोन स्थापित करेंगे एवं वेंडिंग कार्ड्स प्रदान करेंगे
- हम सभी धोबियों के लिए 'धोबी कल्याण बोर्ड' का गठन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उन्हें:
 - लॉन्ड्री यूनिट स्थापित करने के लिए एकमुश्त ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे
 - मशीनीकृत धोबी घाटों की स्थापना करेंगे
 - ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे
 - उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे
- हम 'बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को ₹5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा और ₹10 लाख तक का जीवन बीमा प्रदान करेंगे।
- हम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत, श्रमिकों के कौशल उन्नयन, टूलकिट के लिए ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता और सभी पंजीकृत श्रमिकों को ₹3 लाख तक का ऋण प्रदान करेंगे।
- हम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करेंगे।
- हम इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाले ऑटो ड्राइवर्स के लिए सब्सिडी को ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 करेंगे।
- हम पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और 18 पारंपरिक कारीगर समूहों को लाभ प्रदान करेंगे।



अनुसूचित जाति कल्याण

- हम दिल्ली में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए **डॉ. बी. आर. अंबेडकर स्टाइपेंड योजना** शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आईटीआई (ITI), स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रति माह ₹1,000 का स्टाइपेंड** प्रदान करेंगे।
- हम दिल्ली के अनुसूचित जाति के युवाओं को केंद्र सरकार के **वेंचर कैपिटल फण्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट द्वारा वित्तीय सहायता** उपलब्ध करवाएंगे।
- हम अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए **प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी** करेंगे।
- हम भारत में एनआईआरएफ (NIRF) शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक **अनुसूचित जाति** विद्यार्थी को **₹50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता** प्रदान करेंगे।
- हम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित **सरकारी पदों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी** लाएंगे।
- हम **मैनुअल स्कैवेजिंग को 100% समाप्त** करने के लिए एक मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को **कौशल विकास और वैकल्पिक रोजगार के अवसर** प्रदान किए जाएंगे।

भाषायी समूह

- हम दिल्ली में रहने वाले विविध समाजों जैसे पूर्वांचली, पूर्वोत्तरी आदि अन्य भाषायी समूहों की **सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष** स्थापित करेंगे।
- हम भारतीय परंपराओं का सम्मान करने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए **1,000 छठ घंटों का रखरखाव सुनिश्चित** करेंगे।
- हम पूर्वांचली संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए **द्विवार्षिक पूर्वांचली समारोह का आयोजन** करेंगे।
- हम दिल्ली में सामुदायिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए **पूर्वांचली समाज को भूमि आवंटित** करेंगे।

- हम केंद्र सरकार के साथ मिल कर **छठ पूजा** जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान **पूर्वांचली प्रवासियों** के लिए **स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन** शुरू करेंगे, जिससे उन्हें किफायती और आरामदायक यात्रा मिल सके।
- हम प्रमुख त्योहारों के दौरान स्पेशल **अंतरराज्यीय बस** सेवाएं शुरू करेंगे, जिससे पूर्वांचली और उत्तराखंड के प्रवासियों को घर जाने के लिए सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होंगे।
- हम **पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन** स्थापित करेंगे, जिसमें पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय की स्थायी व्यवस्था होगी।
- हम **पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए छात्रावास** स्थापित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे।
- हम **उत्तराखंड के प्रवासियों** की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए दिल्ली में उत्तरायणी, भित्तौली आदि जैसे विभिन्न **पहाड़ी त्योहारों के भव्य आयोजन के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान करेंगे।
- हम दिल्ली में **हिमाचली कला और सांस्कृतिक अकादमी** स्थापित करेंगे, जो उनकी भाषा, कला और संगीत की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का कार्य करेगी।



सिख समाज

- हम दिल्ली के सभी गुरुद्वारों के ग्रंथियों को प्रति माह ₹20,000 का मानदेय प्रदान करेंगे।
- हम ₹100 करोड़ के निवेश के साथ प्रमुख गुरुद्वारों में अतिरिक्त आवास सुविधाएं, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- हम 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए कल्याण पैकेज शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत:
 - विधवाओं की पेंशन ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 करेंगे
 - स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करेंगे
 - विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देंगे

शरणार्थी कल्याण

- हम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की सभी कॉलोनियों को पहली ही कैबिनेट बैठक में फ्रीहोल्ड संपत्ति का दर्जा देंगे। इससे इन परिवारों को लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता से मुक्ति मिलेगी।
- हम कश्मीर से विस्थापित परिवारों के छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस पर 50% तक की छूट प्रदान करेंगे।
- हम कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन निधि की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत कक्षा 8 तक के छात्रों को ₹2,500 और कक्षा 9-12 तक के छात्रों को ₹3,500 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

दिव्यांगों का कल्याण

- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) में 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक जिले में समर्पित सहायता केंद्र की स्थापना करके दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डीटीसी (DTC) पास, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे।

- हम दिव्यांग पेंशन में वृद्धि करेंगे, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मिलने वाली राशि को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 करेंगे।
- हम दिव्यांगों को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ₹25 लाख तक के कोलैटरल फ्री ऋण प्रदान करेंगे।
- हम सुगम्य भारत मिशन के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए मेट्रो, बस आदि को और सुविधाजनक बनाएंगे।
- हम मिशन पैरालंपिक दिल्ली शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत दिव्यांग एथलीटों की जरूरतों के हिसाब से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ दिल्ली में एक अत्याधुनिक खेल परिसर स्थापित करेंगे और दिव्यांग एथलीटों को सहायता प्रदान करेंगे।

ट्रांसजेंडर

- हम ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे उचित पहचान दस्तावेज जारी करेंगे, जिससे उन्हें आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
- हम केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में 11 गरिमा गृह स्थापित करेंगे और वर्तमान गरिमा गृहों में सुधार करेंगे।
- हम सभी ट्रांसजेंडर नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करेंगे।

मीडियाकर्मियों और वकीलों का कल्याण

- हम दिल्ली के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे।
- हम मीडियाकर्मियों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा तय मान्यता प्रदान करने के कोटे में वृद्धि करेंगे।
- हम वकीलों के लिए ₹10 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस और स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा राशि को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करेंगे।

सैनिक कल्याण

- हम दिल्ली के प्रत्येक जिले में सैनिक बोर्ड स्थापित करेंगे, जो राज्य सैनिक बोर्ड के नेतृत्व में काम करेंगे।



प्रबल अर्थव्यवस्था

आप-दा के वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली अपनी पूरी आर्थिक क्षमता तक पहुंचने में विफल रही है। दिल्ली को अपनी वास्तविक क्षमता का प्रयोग करने के लिए विश्व स्तरीय इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जो नॉलेज आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करेगा। हम दिल्ली की मूल शक्तियों का लाभ उठाकर दिल्ली को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे युवाओं को नौकरियों के अवसर मिलेंगे।

- हम दिल्ली को आने वाले वर्षों में एक **विकसित अर्थव्यवस्था** बनाएंगे एवं भारत को एक **वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाएंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में कम से कम **\$50 बिलियन** का एफडीआई (FDI) आकर्षित करके दिल्ली को **भारत के शीर्ष एफडीआई (FDI) डेस्टिनेशन** में से एक बनाएंगे।
- हम **₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ स्पेशल जोन फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड नॉलेज (SPARK) दिल्ली** विकसित करेंगे, जिसे विश्व भर के फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, आईटी (IT), जीसीसी (GCC) और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे अगले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से **10 लाख से अधिक नौकरियां** सृजित की जा सकेंगी।
 - हम SPARK दिल्ली में फाइनेंस, आईटी (IT) और एआई (AI) के हब स्थापित करेंगे, जिनका लक्ष्य एफडीआई (FDI) आकर्षित करना एवं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना होगा।
 - हम SPARK दिल्ली में विश्व स्तरीय होटल, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि के विकास को प्रोत्साहन देकर इसे **एमआईसीई (MICE)** पर्यटन के लिए एक अग्रणी केंद्र बनाएंगे।
- हम व्यवसाय स्थापित करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे एवं **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दिल्ली को भारत के शीर्ष 3 राज्यों** में शामिल करेंगे।
- हम सभी अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों को अधिकृत करके उन्हें पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- हम दिल्ली औद्योगिक विकास, संचालन एवं रखरखाव अधिनियम की समीक्षा करेंगे।
- हम आप-दा के राज में **सहकारी समितियों में हुए भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे** एवं **दिल्ली सहकारी नीति** बनाएंगे।





व्यापारी वर्ग का कल्याण

आप-दा ने दिल्ली के व्यापारियों पर जटिल नियम, अपर्याप्त आधारभूत संरचना और कारोबार में असहयोग करके उन पर बोझ डाला है। आप-दा के कुशासन के कारण उन्हें अन्य प्रदेशों में स्थानांतरित होना पड़ रहा है। हमारी सरकार दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए नियमों को सरल बनाने, आधारभूत संरचना में सुधार करके और दिल्ली में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

- हम एक **न्यायिक प्राधिकरण** का गठन करेंगे जो 6 महीने के भीतर सील बंद दुकानों को खोलने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और शहर की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- हम एल एंड डीओ (लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस) की सभी लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलेंगे।
- हम व्यापारियों की मांगों को पूरा करने और शिकायतों का निवारण करने के लिए **दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड** स्थापित करेंगे।
- हम दिल्ली में **व्यापार लाइसेंस की वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष** करेंगे।
- हम **दिल्ली रिटेल ट्रेड नीति** तैयार करेंगे, जिसमें सरल नियम, ऋण सुविधा को आसान बनाने और रिटेल ट्रेड से जुड़े छोटे मामलों के डी-क्रिमिनलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- हम **व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बिजली दरों की समीक्षा करके उन्हें कम** करेंगे।
- हम **'बाजार उन्नयन मिशन'** शुरू करेंगे, ताकि सभी प्रमुख बाजारों में बेहतर शहरी नियोजन, बुनियादी सुविधाएं, बेसमेंट पार्किंग और पैदल यात्रियों के लिए विशेष जोन सुनिश्चित किए जा सकें।
- हम ग्रीवेस रिट्रेसल प्रक्रिया को व्यवस्थित करने एवं डिजिटल बनाने तथा ऑडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक **दिल्ली डिजी ट्रेड विकसित** करेंगे।
- हम व्यापारियों के मुद्दों का समय पर हल करने के लिए सभी प्रमुख बाजार क्षेत्रों में **ट्रेड ट्रिब्यूनल्स** स्थापित करेंगे।
- हम दिल्ली में जीएसटी (GST) का भुगतान करने वाले सभी घरेलू व्यापारियों के लिए **दुर्घटना बीमा योजना** शुरू करेंगे।
- हम **प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना** के अंतर्गत सभी पात्र लघु व्यापारियों और कारोबारियों को **₹3,000 प्रति माह पेंशन** प्रदान करते रहेंगे।





सभी के लिए ईज ऑफ लिविंग

केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पीएम आवास, जल जीवन मिशन और सौभाग्य योजना के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे आप-दा दिल्ली के नागरिकों को देने में विफल रही है। हम दिल्ली में मजबूत आधारभूत संरचना बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ जल, नियमित बिजली, किफायती आवास और बाढ़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

स्वच्छ जल

- हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत **हर घर नल से जल** उपलब्ध करवाएंगे।
- हम नागरिकों को **दूषित पानी की समस्या से मुक्ति दिलाकर**, नल से स्वच्छ जल सुनिश्चित करेंगे।
- हम दिल्ली **वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी को 1,500 एमजीडी (MGD) तक बढ़ाएंगे**, इसके अतिरिक्त वाटर स्टोरेज और पम्पिंग क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जलाशय स्थापित करेंगे।
- हम वर्तमान नॉन-रेवेन्यू वाटर को **58% से घटाकर 20%** तक लाएंगे एवं **मुनक नहर में पानी के नुकसान को 18% से कम करके 5%** करेंगे।
- हम **2025 में हरियाणा के सहयोग से वाटर-ट्रीटी का समय पर नवीनीकरण** करेंगे, जिससे पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए यमुना के पानी का उचित हिस्सा मिल सके।
- हम **गंगा से भी अतिरिक्त जल को लाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से उचित समझौते** करेंगे, जिससे दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या की पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

- हम **रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंडवाटर रिचार्ज के उपायों** में तेजी लाएंगे, जिसके लिए घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करेंगे और प्राकृतिक भूजल स्रोतों को पुनर्जीवित करेंगे। साथ ही, दिल्ली के प्राकृतिक जल स्रोत जैसे असोला भाटी क्षेत्र की झीलों, नजफगढ़ झील, सेंट्रल रिज के तालाब, आदि में जल भंडारण क्षमता बढ़ाएंगे।
- हम दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी के कनेक्शन पर वसूले जा रहे **डैवलपमेंट चार्ज की समीक्षा करके उन्हें कम** करेंगे।

बिजली

- हम प्रधानमंत्री **सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** के माध्यम से हर महीने **मुफ्त बिजली** उपलब्ध कराएंगे, जिससे गरीब परिवारों का **बिजली का बिल शून्य** हो जाए।
- हम 2027 तक **दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के सभी भवनों में सोलर रूफटॉप सिस्टम** स्थापित करेंगे।
- हम बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में **व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और फेसलेस सिस्टम द्वारा बिजली कनेक्शन प्रदान** करेंगे।

आवास

- हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ मिल कर अगले 5 वर्षों में गरीब परिवारों को **अतिरिक्त 3.5 लाख पक्के घर** उपलब्ध कराएंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके **हर घर में पाइप गैस कनेक्शन** प्रदान करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के सहयोग से **दिल्ली मास्टर प्लान 2041** कार्यान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से पर्याप्त और किफायती आवास उपलब्ध कराए जा सकें।
- हम आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए **एफएसआई (FSI) नॉर्स में संशोधन** करेंगे, जहां संभव होगा वहां एफएसआई की आवश्यकताओं को खत्म करेंगे, जिससे इमारतों में अधिक मंजिलें बनाई जा सकें।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिल कर **रेरा (RERA) में संशोधन** करेंगे, जिससे मध्यम-वर्गीय परिवारों का घर का सपना पूरा हो। इसमें **पंजीकरण की कीमत को कम करना, निर्माण की लागत को कम करना, आसानी से बिलडिंग का नक्शा पास करवाना** आदि शामिल होंगे।

बाढ़ मुक्त दिल्ली

- हम **₹700 करोड़ के निवेश से दिल्ली को बाढ़ मुक्त** बनाएंगे।
- हम शहरी बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए रियल टाइम डेटा का उपयोग करके **फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम** लागू करेंगे, जिससे समय पर कार्रवाई और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सीवेज ट्रीटमेंट

- हम सुनिश्चित करेंगे कि हर घर में सीवेज की सुविधा हो। हम **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट** की क्षमता 1,000 एमजीडी (MGD) और **कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट** की क्षमता को 220 एमएलडी (MLD) तक बढ़ाएंगे, जिससे 100% सीवेज एवं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सुनिश्चित किया जा सके।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यमुना में उपचारित जल छोड़ने से पहले सभी **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) मानकों को पूरा** करें। वर्तमान में दिल्ली के 37 में से 21 प्लांट मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं।

- हम दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवेज के कनेक्शन पर वसूले जा रहे **डेवलपमेंट चार्ज की समीक्षा करके उन्हें कम** करेंगे।



ग्रामीण दिल्ली का विकास

हम किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने कृषि सहायता, वित्तीय सेवाओं की सुविधा और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की, अब हम दिल्ली के गांवों के विकास को प्राथमिकता देंगे।

समृद्ध कृषि

- हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पात्र किसानों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे, साथ ही ₹6,000 की वार्षिक सहायता को बढ़ाकर ₹9,000 प्रति वर्ष करेंगे।
- हम दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व स्कीम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
- हम ग्रामीण दिल्ली के निवासियों के मालिकाना हक सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों के रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे।



ग्रामीण विकास

- हम सुनिश्चित करेंगे की ग्राम सभा की जमीनों का उपयोग सिर्फ गांववासियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही किया जाए।
- हम दिल्ली के सामुदायिक केंद्रों का नवीनीकरण करेंगे।
- हम ग्राम सभाओं की जमीनों पर आवश्यकतानुसार पार्क, खेल-कूद के मैदान, आदि का निर्माण करेंगे।
- हम दिल्ली के अर्बन-नोटिफाइड गांवों में भूमि स्वामित्व अधिकारों के दाखिल-खारिज मामलों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और एक व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू करेंगे।
- हम गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए:
 - गौशालाओं के संचालन और रखरखाव के लिए गौशाला बोर्ड की स्थापना करेंगे
 - गौशालाओं को चारा, दवाइयां और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने तथा अतिरिक्त गौशालाओं के निर्माण के लिए गौशाला कल्याण कोष का गठन करेंगे

- **भारतीय गाय की नस्लों पर आधारित माइक्रो डेयरियां** स्थापित करने के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान करेंगे
- हम आवारा पशुओं की पहचान करने तथा उन्हें सड़कों से गौशालाओं और पशु आश्रय स्थलों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए **मोबाइल रेस्क्यू यूनिट** स्थापित करेंगे।
- हम दुधारु पशुओं के लिए **नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड जारी करेंगे**, जिसके अंतर्गत उन्हें स्वास्थ्य बीमा और नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी।





विश्वस्तरीय परिवहन

केंद्र की भाजपा सरकार ने पीएम गति शक्ति और भारतमाला परियोजना के माध्यम से पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। जबकि, आप-दा के नेतृत्व में दिल्ली की आधारभूत संरचना खराब हालत में है। परिणामस्वरूप डीटीसी (DTC) बसों की हालत खस्ता है, ट्रैफिक बढ़ गया है और सड़कों की हालत खराब हो गई है। भाजपा हमेशा से आधारभूत संरचना में निवेश करके कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध रही है, जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण सुधारों से झलकता है। हमने कानपुर, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई आदि जैसे विभिन्न शहरों में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की हैं। लेकिन केवल आप-दा की विफलताओं के कारण ही डीएमआरसी (DMRC) समय पर फेज IV को पूरा करने में असमर्थ रही है। हमारा लक्ष्य शहर के प्रमुख स्थानों पर यातायात तथा भीड़भाड़ को कम करना है।

सुगम सार्वजनिक परिवहन

- हमारा लक्ष्य स्वच्छ, किफायती एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क बनाना है, जो अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के माध्यम से निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करेगा। इसके माध्यम से हम यातायात एवं पार्किंग से जुड़ी समस्याओं में सुधार लाएंगे।
- हम दिल्ली को अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स के शीर्ष 10 शहरों में लेकर जाने के लिए ₹20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से एक एकीकृत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क बनाएंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिल कर दिल्ली की यूनिकाइड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करने के लिए डीटीसी (DTC), डीएमआरसी (DMRC), एनसीआरटीसी (NCRTC) और भारतीय रेल की सभी योजनाओं के

समन्वय के लिए यूनिकाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी की स्थापना करेंगे।

- हम परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए लाइट रेल, पॉड-टैक्सी आदि जैसे नवीनतम संसाधनों की व्यवस्था करने की दिशा में प्रयास करेंगे।

सड़क परिवहन

- हम कनेक्टिविटी में सुधार लाने और दिल्ली को 100% ई-बस सिटी में परिवर्तित करने के लिए ई-बसों की संख्या बढ़ाकर 13,000 करेंगे।
- हम बस मार्गों की समीक्षा करके वर्तमान और अंडर-कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइनों और आरआरटीएस (RRTS) के साथ उन्हें एकीकृत करेंगे।
- हम अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 2-टियर बस प्रणाली के अंतर्गत मिडी और मिनी बसों का संचालन करेंगे।

- हम सभी बस डिपो और टर्मिनलों को अपग्रेड करेंगे, साथ ही बड़ी हुई बसों के सही रखरखाव के लिए नए अर्बन एक्सटेंशन रोड-II के आस-पास नए बस डिपो बनाएंगे, जिससे शहर के सभी हिस्सों में बसों का सुचारु संचालन हो सके।
- हम दिल्ली में रह रहे प्रवासियों के सफर को आसान करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों तक विश्व स्तरीय एसी और नॉन-एसी अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करेंगे।
- हम पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य उत्तरी राज्यों में जाने के लिए प्रस्तावित द्वारका और नरेला आईएसबीटी (ISBT) का त्वरित निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित करेंगे।

रेल, मेट्रो और RRTS का विकास

- हम केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली मेट्रो फेज IV को जल्द से जल्द पूरा करेंगे जो वर्तमान में आप-दा के असहयोग के कारण विलंबित हो रहा है।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिल कर दिल्ली मेट्रो के फेज V की प्लानिंग प्रारम्भ करेंगे, जिससे 2026 तक सभी प्रस्तावित मार्गों के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) का कार्य संपन्न हो सके।
- हम डीएमआरसी (DMRC) के साथ मिल कर उचित फ्रीक्वेंसी पर ओवरनाइट मेट्रो चलाएंगे, जिससे बसों के साथ साथ मेट्रो भी जनता को 24x7 उपलब्ध हो।
- हमारी केंद्र सरकार ने न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक आरआरटीएस (RRTS) कॉरिडोर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 2025 में ही हम सराय काले खां से मोदीपुरम तक के पूरे स्ट्रेच पर आरआरटीएस (RRTS) का संचालन सुनिश्चित करेंगे।
- हम मेट्रो और एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से जेवर एयरपोर्ट की दिल्ली तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली-पानीपत एवं दिल्ली-अलवर आरआरटीएस (RRTS) नमो रेल को शीघ्र ही शुरू करेंगे।



सड़क विकास

- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली की **गुरुग्राम और नोएडा से बेहतर कनेक्टिविटी** सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।
- हम सड़कों, फ्लाईओवरों और **एफओबी (FOB)** के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए एक **इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल स्कीम** शुरू करेंगे।
- आप-दा के शासनकाल में परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने के कारण यातायात और भीड़भाड़ की समस्या उत्पन्न हुई है। हम सभी **निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण** करेंगे, जिससे यातायात में राहत मिल सके।
- हम **फ्लाईओवरों के नीचे की जगह का उपयोग करते हुए नागरिक सुविधाएं** जैसे पुस्तकालय, बच्चों के पार्क आदि **स्थापित** करेंगे।

ट्रैफिक एंड पार्किंग मैनेजमेंट

- हम दिल्ली के सभी आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में **यातायात की समस्याएं समाप्त** करने एवं **पर्याप्त पार्किंग** की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत करेंगे।
- हम **आउटर रिंग रोड, एमजी (MG) रोड, एमबी (MB) रोड, आश्रम चौक आदि** सहित दिल्ली के **117 कंजेशन पॉइंट्स की समस्या का समाधान** करने के लिए अतिरिक्त फ्लाईओवर, टनल रोड, बाईपास रोड आदि का निर्माण करेंगे।
- हम सभी प्रमुख बाजारों जैसे **सरोजिनी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर** एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में **मल्टी-स्टोरी एवं अंडरग्राउंड पार्किंग सुविधाएं** प्रदान करेंगे।







सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और पर्यटन का विकास

आप-दा दिल्ली की पर्यटन क्षमता का लाभ उठाने में नाकाम रही है, जिसके कारण विरासत स्थलों और स्मारकों का रखरखाव ठीक से नहीं हो पाया है, पर्यटन जर्जर हालत में है और प्रचार-प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। भाजपा पर्यटन की आधारभूत संरचना को उन्नत करके, इसके प्रतिष्ठित स्थलों को संरक्षित करेगी और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभियान चलाकर, दिल्ली की पर्यटन क्षमता को बढ़ाएगी।

विरासत और संस्कृति को बढ़ावा

- हम महाभारत के प्रसिद्ध पौराणिक महाकाव्य को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए एक भव्य **महाभारत कॉरिडोर** विकसित करेंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों के साथ साझेदारी भी करेंगे।
- हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर एक **ग्लोबल दिल्ली डिजिटल कैम्पेन** शुरू करेंगे, जिसमें ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से दिल्ली की संस्कृति, त्योहारों और पर्यटन को प्रदर्शित किया जाएगा।
- हम दिल्ली की विविध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत के संगीत, नृत्य, भोजन और हस्तशिल्प को मिलाकर एक महीने तक चलने वाला **'वार्षिक दिल्ली शीतकालीन महोत्सव'** आयोजित करेंगे।
- हम एएसआई (ASI) के अंतर्गत न आने वाले दिल्ली के सभी भूले हुए और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, संवर्धन और विकास के लिए **₹50 करोड़** के बजट के साथ **'विरासत पुनरुद्धार अभियान'** शुरू करेंगे।
- हम **₹300 करोड़** के आवंटन के साथ एक **'मदन लाल खुराना अर्बन हेरिटेज मिशन'** शुरू करेंगे, जिसमें विशेष जातीय समुदायों से जुड़े एवं महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य रखने वाले स्थलों पर ध्यान दिया जाएगा।
- हम दिल्ली के सभी मंदिरों के पुजारियों को प्रति माह **₹20,000 का मानदेय** प्रदान करेंगे।
- हम दिल्ली में केंद्र सरकार की **'वरिष्ठ कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना'** लागू करेंगे, जिसके तहत **वरिष्ठ कलाकारों को ₹6,000 प्रति माह** की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- हम केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके एनजीएमए (NGMA) की तर्ज पर देश भर के पारंपरिक कला रूपों को प्रदर्शित करने के लिए एक **राष्ट्रीय पारंपरिक कला गैलरी** स्थापित करेंगे।
- हम हर वर्ष दिल्ली में **भव्य संस्कृत महोत्सव** का आयोजन करेंगे।

- हम हर वर्ष **संस्कृत अनुसंधान, प्राचीन भारतीय शास्त्रों एवं ग्रंथों के अध्ययन** के लिए **विशेष अनुदान** प्रदान करेंगे।
- हम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर **पर्याप्त संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति** सुनिश्चित करेंगे।
- हम **भगत सिंह और उनके योगदान को समर्पित एक गैलरी** स्थापित करेंगे, जिससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी विरासत को सम्मानित किया जा सके।

विकसित पर्यटन

- हम 2030 तक दिल्ली आने वाले **घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी** करेंगे।
- हम **₹100 करोड़ के बजट से चांदनी चौक को दिल्ली के पहले आदर्श बाजार में परिवर्तित** करेंगे, जिसमें स्वच्छता, परिवहन, भूमिगत वायरिंग और अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- हम दिल्ली के सभी **व्यावसायिक क्षेत्र जैसे मजनु का टीला, हौज खास आदि एवं प्रमुख स्मारकों के आसपास सुरक्षित रात्रि बाजार और फूड स्ट्रीट** विकसित करेंगे।

- हम इंडिया गेट, लाल किला और कुतुब मीनार जैसे पर्यटन स्थलों पर **गाइडेड नाईट हेरिटेज वॉक** का आयोजन करेंगे।
- हम पर्यटकों की आसानी के लिए दिल्ली के सभी स्मारकों में **मल्टी-एंट्री कार्ड** शुरू करेंगे।
- हम दिल्ली को **एमआईसीई (MICE) पर्यटन के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र** के रूप में स्थापित करेंगे।
- हम दिल्ली में व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को **'इंडस्ट्री' का दर्जा** देंगे।
- हम सभी **एसआई (ASI)** स्मारकों पर प्रशिक्षित बहुभाषी पर्यटक गाइड की व्यवस्था करेंगे, जिन्हें अतुल्य भारत पोर्टल से बुक किया जा सकेगा।
- हम दिल्ली में **टूर गाइडों के डिजिटल स्किल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन** को सुनिश्चित करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर (आईआईटीएफ) सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का विस्तार करेंगे।





स्वच्छ एवं हरित दिल्ली

आप-दा के राज में दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के दावे खोखले साबित हुए हैं। प्रदूषण ही नहीं, सरकार बड़े-बड़े वादे करने के बावजूद यमुना नदी को भी साफ करने में नाकाम रही है। भाजपा प्रदूषण मुक्त दिल्ली और यमुना नदी की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में से एक बने और यमुना नदी फिर से गौरवान्वित हो।

- हम केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर **यमुना रिवर फ्रंट** का विकास करेंगे, जिसमें यमुना के किनारे 24x7 व्यावसायिक प्रतिष्ठान, इंटरैक्टिव शो, नाट्य स्थल आदि जैसी मनोरंजन की सुविधाएं होंगी।
- हम **यमुना कोष के माध्यम से यमुना नदी को पुनर्जीवित** करेंगे, जिसे आप-दा ने पिछले 10 वर्षों से नजरअंदाज किया है। इसके अंतर्गत हम:
 - बारापुला, शाहदरा, गाजीपुर आदि अन्य **नालों के पानी को यमुना में छोड़ने से पहले उसका पूरा ट्रीटमेंट** करेंगे
 - वर्तमान में नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी **साहिबी नदी में मिलने वाले सभी नालों के पानी को ट्रीट करेंगे**
 - **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का 1,000 एमजीडी (MGD) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का 220 एमएलडी (MLD) तक विस्तार** करेंगे
- यमुना के किनारों पर बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कॉरिडोर एवं वेटलैंड के साथ **रिवर बैंक बफर जोन** बनाएं
- यमुना में **शून्य औद्योगिक एमीशन** सुनिश्चित करेंगे
- **वार्षिक यमुना महोत्सव** का आयोजन करेंगे
- हमारा लक्ष्य दिल्ली को देश का **सबसे स्वच्छ महानगर** बनाकर **स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान** पर पहुंचाना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम:
 - **गाजीपुर, ओखला और भलस्वा** के 'कचरे के पहाड़ों' को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाएं, और इनका बांसेरा पार्क की तर्ज पर पुनर्विकास करेंगे
 - **भविष्य में कचरे के पहाड़ न बनें इसके लिए** सूखा और गीला कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे
 - **कचरा संग्रहण क्षमता बढ़ाने** के लिए दिल्ली नगर निगम के साथ मिल कर काम करेंगे
 - मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वच्छता से जुड़ी **शिकायतों का रियल टाइम पर समाधान** करेंगे

- नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करेंगे
- हम दिल्ली क्लीन एयर मिशन की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य 2030 तक एवरेज एक्व्यूआई (AQI) को आधा करना और खराब AQI वाले दिनों को कम करना होगा। हमारा लक्ष्य PM 2.5 और PM10 के स्तर को 50% तक कम करना है। इस मिशन के अंतर्गत हम:
 - प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़क सफाई मशीनें तथा प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में जल छिड़काव मशीनें तैनात करेंगे
 - आनंद विहार, आरके (RK) पुरम और मुंडका जैसे प्रदूषित क्षेत्रों में अतिरिक्त सड़क सफाई मशीनें और जल छिड़काव मशीनें तैनात करेंगे
 - सड़को पर धूल नियंत्रित करने के लिए 500 किलोमीटर कच्ची सड़कों को पक्का करने को प्राथमिकता देंगे
 - धूल के नियंत्रण पर अधिकतम प्रभाव के लिए चौराहों और प्रमुख सड़कों पर वायू (WAYU) यंत्र स्थापित करेंगे
- हम दिल्ली को सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए 50% वाहनों को इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन देंगे एवं पब्लिक ईवी (EV) चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेंगे।
- हम दिल्ली के पहाड़ों और झीलों को पुनर्जीवित करेंगे और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाएंगे।
- हम अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट, अर्बन फॉरेस्ट्स और वर्टिकल गार्डन विकसित करके हरित क्षेत्र का विस्तार करेंगे।
- हम सभी आरडब्ल्यूए (RWA) के साथ सहयोग करके ओपन जिम और पार्कों के निर्माण एवं देख-रेख पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके द्वारका में बन रहे भारत वंदना पार्क की तर्ज पर नए पार्कों का निर्माण करेंगे।









भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश





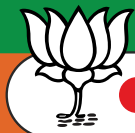
संकल्प पत्र डाउनलोड करने हेतु



QR कोड को स्कैन करें



कमल का बटन दबाएं



भाजपा को जिताएं